**भारत सरकार**

**वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय**

**औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्या: 987**

**बुधवार 29 जुलाई, 2015 को उत्तर दिए जाने के लिए**

**दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड को परियोजना के क्रियान्वयन में पेश आ रही समस्याएं**

**अता.प्र.सं. 987. श्री दिलीपभाई पंडयाः**

**क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा विकास निगम लिमिटेड (डीएमआईसीडीसी) को परियोजना के क्रियान्वयन में समस्याएं पेश आ रही हैं और वह केन्द्र सरकार से सहायता मांग रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली और मुंबई के बीच सात 'ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज' स्थापित करने के प्रयोजन से बनी बृहद परियोजना का निष्पादन करने वाली कंपनी द्वारा हस्ताक्षरित कुछ समझौतों को लेकर कुछ चिंताएं/समस्याएं व्यक्त की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) डीएमआईसीडीसी के प्रस्ताव के शीघ्र क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वाणिज्‍य और उद्योग राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

**(क) और (ख):** डीएमआईसी परियोजना संबंधित राज्‍य सरकारों की भागीदारी से कार्यान्‍वित की जा रही है। परियोजना विकास क्रिया-कलाप सतत रूप से किए जा रहे हैं।

**(ग) और (घ):**  जी, नहीं।

**(ङ):**  भारत सरकार ने डीएमआईसी परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्‍वयन के लिए डीएमआईसीडीसी के माध्‍यम से परियोजना विकास क्रियाकलाप, मास्‍टर प्‍लानिंग, विस्‍तृत इंजीनियरिंग, हितधारक करार/राज्‍य सहायता करार पर हस्‍ताक्षर करने, एसपीवी के गठन तथा एसपीवी को निधि जारी करने जैसे विभिन्‍न कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्‍ताव किया है।

\*\*\*\*\*\*\*